



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]  
No. 133]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चैत्र 10, 1927  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

सं. 17/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 196(अ)।—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 कहा जाए।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे।
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) में, नियम 8 में,—  
(क) उपनियम (3) और इसके परन्तु और उदाहरणों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—  
“(3) यदि निर्धारिती निर्धारित तारीख तक राशि अदा करने में विफल रहता है तो बकाया राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक नियत तारीख के बाद प्रथम दिन से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए बकाया राशि पर अधिनियम की धारा 11क ख के अंतर्गत अधिसूचना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज सहित बकाया राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगी।”।  
(ख) ऐसे प्रतिस्थापित उपनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
“(3क) यदि निर्धारिती उपनियम (2) में विहित तारीख तक शुल्क के भुगतान में चूक करता है और यह उक्त तारीख से तीस दिन की अवधि से परे निर्वहण किया जाता है तो निर्धारिती इस संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के संप्रेषण की तारीख से आरंभ होने वाली दो माह की अवधि के लिए अथवा ऐसी तारीख जिस पर इसके ब्याज सहित सभी बकाये चुकाए जाते हैं, जो भी बाद में हो, उपनियम के अंतर्गत मासिक किस्तों में शुल्क को अदा करने की सुविधा से वंचित होगा और इस अवधि के दौरान सेनेट क्रेडिट नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्धारिती को चालू खाते में जामा द्वारा प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क अदा करना आवश्यक होगा और ऐसा करने में विफल रहने पर यह समझा जाएगा कि ऐसा माल शुल्क के भुगतान के बिना निकासित किया गया है और परिणाम और इन नियमों में यथा-प्रावधान किए गए जुमाने का अनुगमन करना होगा।”।

2. उक्त नियमावली के नियम 12 में, उपनियम (2) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगा, अर्थात् :—
  3. “(3) सक्षम अधिकारी उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा दायर विवरणी में निहित सूचना और ऐसी आगे की जांच-पड़ताल जो वह आवश्यक समझे, के आधार पर बोर्ड द्वारा विहित ढंग में हटाए गए माल पर निर्धारिती द्वारा निर्धारित शुल्क की सटीकता की संयोक्ता करता है।
    - (4) प्रत्येक निर्धारिती को सक्षम अधिकारी को सभी दस्तावेजों और रिकार्डों को ऐसे अधिकारी द्वारा जब कभी अपेक्षित हों सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने होंगे।”।
4. उक्त नियमावली के नियम 22 में,—
  - (क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
    - “(2) प्रत्येक निर्धारिती और प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के डीलर निम्न की दो प्रतियों में एक सूची उपनियम (1) के अंतर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
      - (i) निविष्टियों और कारखानागत माल सहित माल की प्राप्ति, खरीद, विनिर्माण, भण्डारण, बिक्री अथवा सुपुर्दगी जैसा भी मामला हो, के संबंध में तैयार किए गए और रखे गए लेन देन के लेखांकन;
      - (ii) निविष्ट सेवाओं के भुगतान और उनकी प्राप्ति अथवा खरीद के संबंध में लेन देन के तैयार किए गए और रखे गए लेखांकन के लिए सभी रिकार्ड; और
      - (iii) ट्राइल अधिशेष अथवा इसके समक्ष सहित सभी वित्तीय रिकार्ड और विवरण।”

“स्पष्टीकरण” “प्रथम चरण डीलर” और “द्वितीय चरण डीलर” का आशय वही होगा जो सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में उनको सौंपा गया है।”

[फा. सं० 224/1/2005-के.उ.शु. 6]

नीरव कुमार मल्लिक, अवर सचिव

**टिप्पणी :**— मूल नियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में, अधिसूचना सं. 4/2002-के.उ.शु. (गै.टै.), दिनांक 1 मार्च, 2002 [सा.का.नि. 143(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002] के द्वारा प्रकाशित हुई थी और अधिसूचना सं. 12/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) दिनांक 1 मार्च, 2005 [सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005] के द्वारा अन्तिम बार संशोधित की गई थी।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2005

No. 17/2005-CENTRAL EXCISE (N.T.)

**G.S.R. 196(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise ( Second .Amendment) Rules, 2005.
  2. They shall come into force on and from 1st April, 2005.
2. In the Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8,—
- (A) for sub-rule (3), and the proviso and the illustrations thereto, the following shall be substituted namely :—
- “(3) If the assessee fails to pay the amount of duty by due date, he shall be liable to pay the outstanding amount along with interest at the rate specified by the Central Government vide notification under Section 11AB of the Act on the outstanding amount, for the period starting with the first day after due date till the date of actual payment of the outstanding amount.”

(B) after sub-rule (3) so substituted, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3A) If the assessee defaults in payment of duty by the date prescribed in sub-rule (2) and the same is discharged beyond a period of thirty days from the said date, then the assessee shall forfeit the facility to pay the duty in monthly instalments under sub-rule (1) for a period of two months, starting from the date of communication of the order passed by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, in this regard or till such date on which all dues including interest thereof are paid, whichever is later, and during this period notwithstanding anything contained in sub-rule (4) of rule 3 of CENVAT Credit Rules, 2004, the assessee shall be required to pay excise duty for each consignment by debit to the account current and in the event of any failure, it shall be deemed that such goods have been cleared without payment of duty and the consequences and penalties as provided in these rules shall follow.”.

3. In rule 12 of the said rules, after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:—

“(3) The proper officer may on the basis of information contained in the return filed by the assessee under sub-rule (1), and after such further enquiry as he may consider necessary, scrutinize the correctness of the duty assessed by the assessee on the goods removed, in the manner to be prescribed by the Board.

(4) Every assessee shall make available to the proper officer all the documents and records for verification as and when required by such officer.”.

4. In rule 22 of the said rules,—

(A) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Every assessee, and first stage and second stage dealer shall furnish to the officer empowered under sub-rule (1), a list in duplicate, of—

- (i) all the records prepared and maintained for accounting of transaction in regard to receipt, purchase, manufacture, storage, sales or delivery of the goods including inputs and capital goods, as the case may be;
- (ii) all the records prepared and maintained for accounting of transaction in regard to payment for input services and their receipt or procurement; and
- (iii) all the financial records and statements including trial balance or its equivalent.”.

(B) in sub-rule (3), for the words “Every assessee”, the words “Every assessee, and first stage and second stage dealer” shall be substituted.

(C) after sub-rule (3), the following Explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation.—For the purposes of this rule, “first stage dealer” and “second stage dealer” shall have the meanings assigned to them in CENVAT Credit Rules, 2004.”.

[F. No. 224/1/2005 CX 6]

NEERAV KUMAR MALICK, Under Secy.

**Note :**—The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* notification No. 4/2002-CE (N.T.), dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 143(E), dated the 1st March, 2002] and was last amended *vide* notification No. 12/2005-CE (N.T.), dated the 1st March, 2005 [G.S.R. 135(E) dated the 1st March, 2005].